

भारतने आतंक के अड़ों को किया ध्वस्त: प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन

ऑपरेशन 'सिंदूर' में १०० से अधिक आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तानी ढांचे को तगड़ा झटका



नई दिल्ली, १२ मई: संवाददाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात ८ बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता की घोषणा की। अपने जोशीले और भावनात्मक भाषण में उन्होंने कहा, हमारे वीर सैनिकों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के लक्ष्यों को हासिल करने में अभूतपूर्व साहस दिखाया है। आज मैं उनके शौर्य को नमन करता हूँ और इस वीरता को देश की हर माँ, बहन और बेटों को समर्पित करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई का नाम नहीं, बल्कि यह देश की जनता के आत्म-सम्मान और भावनाओं का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमने सुरक्षा बलों को आतंक के विरुद्ध खुली छूट दी थी, और उन्होंने आतंकवादियों के उन सभी ठिकानों को तबाह कर दिया जो हमारी बेटियों के 'सिंदूर' को मिटाने का दुस्साहस कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इस सैन्य कार्रवाई में १०० से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा, जब हमारे मिसाइलों और ड्रोन ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो सिर्फ इमारतें नहीं गिरीं, उनके हाँसले भी चकनाचूर हो गए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा: खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब पाकिस्तान से बातचीत होगी तो केवल कब्ज़ा किए गए कश्मीर (पाक अधिकृत कश्मीर) पर होगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह न सिर्फ युद्ध का समय नहीं है, बल्कि अब आतंकवाद के लिए भी कोई जगह नहीं है - न भारत में, न दुनिया में। पृष्ठभूमि (विस्तार): 'ऑपरेशन सिंदूर' भारत की सशस्त्र सेनाओं द्वारा हाल ही में पाकिस्तान की सीमा में की गई एक लक्षित सैन्य कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य सीमापार चल रहे आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को ध्वस्त करना था। यह कार्रवाई नियंत्रण रेखा (डिउ) के पार स्थित पंजाब, बालाकोट और पीओके के अन्य क्षेत्रों में की गई।

भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना की संयुक्त कमान द्वारा इसे अंजाम दिया गया। इसमें आधुनिक ड्रोन, सटीक गाइडेड मिसाइलें और साइबर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ। प्रतिक्रिया: इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और जखउ से आपातकालीन बैठक की मांग की है, वहीं भारत में सभी प्रमुख दलों ने सेना की बहादुरी की प्रशंसा की है। मुंबई, दिल्ली, पुणे, लखनऊ समेत कई शहरों में नागरिकों ने मोमबत्तियाँ जलाकर सेना का आभार प्रकट किया।

ट्रंप की मध्य पूर्व यात्रा से पहले शांति का संदेश

हमास ने अमेरिकी-इजराइली बंधक को रिहा करने की घोषणा की

गाज़ा/वॉशिंगटन, १२ मई: मध्य पूर्व में चल रहे तनावपूर्ण हालात के बीच एक सकारात्मक संकेत देते हुए, हमास ने अपनी हिरासत में मौजूद इजराइली-अमेरिकी नागरिक एडन एलेक्जेंडर को रिहा करने की घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को मध्य पूर्व के दौरे पर पहुंच रहे हैं।

हमास का कहना है कि यह रिहाई गाज़ा में मानवीय सहायता पहुंचाने के किसी संभावित समझौते की दिशा में एक सद्भावनापूर्ण कदम है। उल्लेखनीय है कि इजराइल द्वारा पिछले ७० दिनों से गाज़ा की पूर्ण घेराबंदी की जा रही है, जिससे वहाँ भारी मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है।

बीबीसी को दिए बयान में

गाज़ा में मानवीय राहत और संवाद की संभावनाओं को मिला बल

हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संगठन अमेरिका के एक उच्च अधिकारी से क़तर में प्रत्यक्ष बातचीत कर रहा है। रिहाई का निर्णय इसी वार्ता प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है।

इजराइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी पुष्टि की है कि अमेरिका ने उन्हें सूचित किया है कि एडन एलेक्जेंडर की रिहाई शीघ्र होने वाली है।

इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर सोशल पर एक संदेश जारी कर एलेक्जेंडर की रिहाई की पुष्टि की और इसे नेक नीयत और शांति की दिशा में उठाया गया कदम बताया।

एडन एलेक्जेंडर हमास की कैद में जीवित बचे इकलौते अमेरिकी नागरिक माने जा रहे थे।

इस कदम को ट्रंप प्रशासन के कूटनीतिक प्रयासों की सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रंप के आगामी मध्य पूर्व दौरे को अब अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है।

यह रिहाई शांति, संवाद और मानवीय मूल्यों की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। ट्रंप की यात्रा से पहले यह कदम मध्य पूर्व में तनाव कम करने और गाज़ा में राहत पहुंचाने के रास्ते खोल सकता है।

तूफानी बारिश और तेज़ हवाओं से हुए नुकसान का विधायक संदीप क्षीरसागर ने किया दौरा

प्रशासन को तुरंत पंचनामा करने के निर्देश

बीड, १२ मई (प्रतिनिधि): बीड विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को आई तेज़ हवाओं और अचानक हुई मुसलधार बारिश से किसानों और नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का जायज़ा लेने के लिए विधायक संदीप क्षीरसागर ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रशासन को निर्देश दिया कि तुरंत पंचनामा कर राहत कार्य शुरू किया जाए। सोमवार (१२ मई) को बीड शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ आंधी और बारिश ने कहर बरपाया, जिससे कई जगहों पर खेती, मकान, और बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। विधायक क्षीरसागर ने आपदा के तुरंत बाद विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचकर हालात की समीक्षा की।



उन्होंने कहा कि बारिश और तेज़ हवाओं के कारण खेतों में फसलों को नुकसान पहुँचा है और कई घरों की छतें उड़ गई हैं या दीवारें गिर गई हैं। उन्होंने जिलाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि नुकसान का

आकलन शीघ्र किया जाए और सरकार की ओर से पीड़ितों को त्वरित सहायता दी जाए। तेज़ आंधी के चलते बिजली आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिर गए और तार टूट गए, जिससे बीड

शहर और उसके आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए विधायक संदीप क्षीरसागर ने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

जंग रोकने के पीछे व्यापार की शर्त थी-राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

हमने कहा-अगर जंग रोकोगे तो व्यापार होगा, नहीं तो कुछ नहीं : व्हाइट हाउस में ट्रंप का बड़ा खुलासा



वॉशिंगटन डी.सी., १२ मई (ईटीवी भारत):

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह खुलासा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सीज़फायर समझौते के पीछे अमेरिका द्वारा व्यापार को दबाव के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों से साफ कहा गया था कि अगर वे लड़ाई रोकेंगे, तो

अमेरिका व्यापार करेगा, वरना कोई व्यापार नहीं होगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा:

हमने दोनों देशों से कहा - 'आओ, हम आपसे बहुत व्यापार करेंगे, लेकिन लड़ाई बंद करो। अगर बंद करोगे तो व्यापार होगा, नहीं तो कुछ नहीं।' किसी ने व्यापार को इस तरह से कभी इस्तेमाल नहीं किया, जैसा हमने किया। और अचानक उन्होंने कहा कि हम इसे रोक रहे हैं। व्यापार एक बड़ी वजह थी।

इस बयान के बाद यह बात स्पष्ट

होती है कि अमेरिका ने कूटनीतिक दखल के साथ-साथ आर्थिक हितों के जरिये भी भारत-पाक युद्धविराम में निर्णायक भूमिका निभाई।

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु संघर्ष को रोकने, और मौजूदा सीज़फायर को स्थायी शांति की दिशा में एक कदम बताया।

गौरतलब है कि २२ अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए

आतंकी हमले के बाद भारत ने ७ मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी हमले किए, लेकिन ११ मई को युद्धविराम की घोषणा हुई, जिसे सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक किया।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी मध्यस्थता की सराहना की और अमेरिका के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ाने की इच्छा जताई है।

तस्वीर नामा सुपर "परि निंदा"

युं तो ये परिंदा खानदानी है। पर हरकतें सब शैतानी है। खाता है शौक से वो बारूद शांति शांति उसकि वानी है।



- काजी मखदूम
दैनिक तामीर
९२७०५७४४४४

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

सहकार कानून में संशोधन के लिए समिति का गठन होगा-मुख्यमंत्री फडणवीस

सहकार संवाद मंच पर शरद पवार, नितिन गडकरी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद



रिपोर्ट: जमीर काजी, तभा न्यूज सेवा मुंबई, १२ मई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार मौजूदा सहकार कानून में आवश्यक संशोधन के लिए एक विशेष समिति का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि सहकार क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक घटक को न्याय मिलना चाहिए और बदलते समय के अनुसार नई धाराओं और प्रकरणों को कानून में शामिल करना आवश्यक है।

यह घोषणा उन्होंने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागार में आयोजित सहकार का सशक्तिकरण और राज्य सरकार की नीति विषयक परिसंवाद के दौरान की।

यह कार्यक्रम दखन का उठाव, सहकार की 'मुहूर्तवेद', १५०वीं वर्षगांठ और अंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।

इस मौके पर मंच पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार मौजूद थे। कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा कि अविकसित सहकारी संस्थाओं को पुनः सक्रिय बनाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सहकारी बैंकों ने कोर बैंकिंग सिस्टम और तकनीकी नवाचारों को अपनाकर लरपड़-छपस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों ने वित्तीय एकीकरण के दौर में भी अपना अस्तित्व बनाए रखा और बेहतर सेवा दी है। उन्होंने बताया कि १२ मई १८७५ को पुणे ज़िले के सुपा गांव में साहूकारी व्यवस्था के खिलाफ हुआ जनआंदोलन ही महाराष्ट्र की सहकार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, और आज इस घटना को १५० वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार स्वतंत्र सहकार मंत्रालय की स्थापना की, जिससे सहकार आंदोलन को नया बल मिला है। फडणवीस ने आगे कहा कि चीनी मिलें अब केवल चीनी नहीं, बल्कि उप-उत्पाद भी बना रही हैं और इससे वे वैश्विक

प्रतिस्पर्धा में टिक पा रही हैं। केंद्र सरकार ने इथेनॉल नीति और एमएसपी जैसे मामलों में लगातार सुधार किए हैं। राज्य सरकार की भूमिका यह सुनिश्चित करने की है कि शेतकरी ही अपने कारखानों के मालिक बने रहें। उन्होंने कहा कि सूतगिरनियों को बिजली की दरें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बाधा बन रही हैं, इसलिए उन्हें सौर ऊर्जा पर शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की कुल सहकारी संस्थाओं में से ५०% सहकारी हाउसिंग सोसायटियां हैं, जिनके लिए सहकार कानून में विशेष प्रकरण शामिल किया गया है। स्वयं-पुनर्विकास योजनाओं के अंतर्गत उन्हें १७ प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्र में सहकार मंत्रालय बनने के बाद देशभर में सहकार सुधारों की लहर शुरू हुई है। अजित पवार ने सुझाव दिया कि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक को सहकार आंदोलन के इतिहास पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सहकार आंदोलन को और मजबूत करना जरूरी है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुझाव दिया कि वर्तमान कंपनी कानून और सहकार कानून के बीच समन्वय बैठकर एक नया समेकित कानून बनाया जाए।

साहूकारी व्यवस्था का विकल्प बना सहकार आंदोलन-शरद पवार

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा कि १२ मई १८७५ को पुणे के सुपा गांव में साहूकारों के खिलाफ हुआ आंदोलन ही सहकार आंदोलन की जन्मस्थली था। उस समय शोषण के चलते किसान हताश और गरीब हो गए थे। सहकार आंदोलन ने उन्हें इससे मुक्ति दिलाई। उन्होंने बताया कि राज्य सहकारी बैंक ने उस दौर में जो योजनाएं शुरू की थीं, वे आज भी चल रही हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को फिर से ऊर्जावान बनाना वक्त की जरूरत है।

इस अवसर पर राज्य सहकारी बैंक की आर्थिक रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में सहकार क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मानवता अभी जीवित है...



जली उषाताई..दौड़ा फारुक भाई

जलगांव (अकिल खान ब्यावली) आज जहां चारों ओर नफरत व घृणा का माहौल नज़र आ रहा है इसान इंसान मारने काटने को दौड़ रहा है वहीं दिल को छू लेने वाली घटनाएं भी इतिहास बनकर हमारे सामने आ रहि है, हाल ही में जलगांव नगरी में मुस्लिम मनियार बिरादरी के फारुक शेख ने अपनी हिंदू बहन उषा मोरे जो,रामेश्वर कॉलोनी में रहती है,उनकी समय पर सहायता करके मानवता का एक अद्वितीय उदाहरण पेश किया है,इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल सोनवणे जो एस एम व्हाट्स एप समुह के एडमिन है ने अपने समुह पर ईशा मोरे नामी महिला की अपने ही घर में आग से पुरा शरीर जल जाने से उसे शहर के निजी सारा अस्पताल दाखिल कराने पर उनके इलाज मे आर्थिक सहायता का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो एस.एम.व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यमसे आर्थिक सहायता की अपील की गई थी इस अपील को देखकर फारुक शेख ने स्वयं पहल कर अपने साथियों के साथ अस्पताल जाकर उस हिन्दू बहन की स्वास्थ्य संबंधी पृष्ठताछ की और उनकी लड़की आरती को धीर दिया और उन्हें रु. ५ हजार राशिका अस्पताल के नाम का चेक सुपुर्द किया, अस्पताल के संचालक तथा

मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मिनाज पटेल से भी बात चित की और उन्होंने जो पेशेंट को तुरंत वैद्यकीय सहायता दी उसके प्रति उनका भी आभार व्यक्त किया।

मानवता की जीत इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता की भावना सबसे महत्वपूर्ण है. यह घटना हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में एक दूसरे की सहायता करना और मानवता का परिचय देना हमारा कर्तव्य है

सामाजिक एकता का संदेश

इस प्रकार की घटनाएं समाज में एकता और सौहार्द का संदेश देती हैं,यह हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी एक ही मानव परिवार के अंग हैं और हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग का भाव रखना चाहिए.

आभार और प्रशंसा हम मुस्लिम मनियार बिरादरी और फारुक भाई की इंसानियत साथ ही डॉ मिनाज पटेल साहब की सेवा की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने इस कठिन समय में अपनी हिंदू बहन की सहायता की.उनकी इस पहल ने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है और हमें प्रेरित किया है कि हम भी अपने आसपास के लोगों की सहायता के लिए आगे आएँ.

मुस्लिम समाज को महिला शिक्षा पर देना चाहिए विशेष ध्यान-पुलिस अधीक्षक हसन गौहर

कळमनुरी (प्रतिनिधि) – मुस्लिम समाज को लड़कियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यह विचार हिंगोली जिले के पुलिस अधीक्षक हसन गौहर ने व्यक्त किए। वे रविवार को आयोजित शेखताई तालिमी फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम में बोल रहे थे।

यह कार्यक्रम कळमनुरी के



स्थानीय स्कूल में आयोजित किया गया था। इसमें शेखताई तालिमी फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अब्दुल मुद्दै, मौलाना गफ्फार, मौलाना यासीन, मौलाना शमीम, कर्नल सोहेल कुरैशी,

प्रोफेसर मुजिब कुरैशी आदि उपस्थित थे। अपने संबोधन में एसपी हसन गौहर ने कहा कि मुस्लिम समाज को शिक्षा की अहमियत को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, आज जब हम

राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के बीच समन्वय की बैठक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा: मिलकर करेंगे काम



मुंबई, १२ मई: भारत-पाक तनाव की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र सरकार और देश की सुरक्षा एजेंसियों के बीच आज एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वर्षा निवास पर संपन्न हुई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार अब सुरक्षा बलों के साथ और अधिक समन्वय से काम करेगी।

इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौमिक, भारतीय सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल पवन चड्ढा, कर्नल संदीप सील, नौसेना की ओर से रियर एडमिरल अनिल जगुी और कमांडर नितेश गर्ग तथा वायुसेना की ओर से एयर वाइस मार्शल रजत मोहन उपस्थित थे। इसके अलावा आरबीआई, जेएनपीटी, बीपीटी, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल

स्टॉक एक्सचेंज, एटीएस, होमगार्ड्स आदि संस्थानों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को जिस दृढ़ता और सटीकता से अंजाम दिया है, वह अभूतपूर्व है। मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूँ। मुंबई जैसा शहर, जो देश की आर्थिक राजधानी है, पहले भी हमलों का शिकार रहा है और हमारे दुश्मनों ने इसे प्रतीकात्मक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला बताया। ऐसे में आने वाले समय में हमें पूर्ण शक्ति से तैयार रहना होगा।

बैठक में गुप्तचर सूचना के आदान-प्रदान, आधुनिक तकनीक के उपयोग और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सतर्कता बरतने पर चर्चा हुई। साथ ही राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा बलों को अपेक्षित सहायता और तेज समन्वय प्रणाली स्थापित करने की

दिशा में भी निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा रक्षा बलों के अधिकारी मिलकर अधिक समन्वय से काम करेंगे।

इस बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अधिनी भीडे, श्रीकर परदेशी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबालसिंह चहल, पुलिस महानिदेशक रश्मी शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त विपिन शर्मा, नागरी सुरक्षा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रभात कुमार, खुफिया विभाग के एआईजी शिरीष जैन, आपदा प्रबंधन की अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी, मुंबई शहर और उपनगर के जिलाधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

एसटी में जल्द ही होगी भर्तियां, २५ हजार नई बसों के संचालन के लिए बढ़ेगी मानव संसाधन की आवश्यकता

एसटी महामंडल की निदेशक मंडल बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी

विशेष प्रतिनिधि, मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एसटी) को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से आने वाले वर्षों में २५,००० स्वामित्वाधीन नई बसें खरीदी जाएंगी। इन बसों को संचालन में लाने के लिए चालक और वाहक सहित अन्य वर्गों के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को एसटी महामंडल की ३०७वीं संचालक मंडल बैठक में स्वीकृति दी गई है।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने वर्ष २०२४ तक एसटी में भर्ती पर रोक लगाई थी। हालांकि, निकट भविष्य में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नई बसों के संचालन के लिए चालक, वाहक एवं तकनीकी कर्मियों की भर्ती

आवश्यक है। यह प्रस्ताव राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। आने वाले समय में बसों की संख्या में वृद्धि के अनुसार कर्मचारियों की नई आकृति संरचना को भी मंजूरी दी जाएगी और उसी के अनुरूप आगे की भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी।

वर्तमान में एसटी के कई विभागों में कुशल मानव संसाधन की कमी देखी जा रही है। विशेष रूप से एसटी की भूमि पर झड़झ मॉडल (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) के तहत विकसित होने वाली परियोजनाओं को देखते हुए निर्माण विभाग में कुशल अभियंताओं की जरूरत होगी। इस

कारण, रिक्त अभियंता पदों को अनुबंध आधारित या सीधी सेवा भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा कर आवश्यक पदों को जल्द भरें। एसटी को सशक्त बनाने के लिए कुशल मानव संसाधन के साथ-साथ तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारियों की भी आवश्यकता होगी, इसी को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति और युद्धविराम बनाए रखने पर जोर

नई दिल्ली, १२ मई:

भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस (उन्नखजी) के बीच सोमवार को दूसरी बार हॉटलाइन पर बातचीत हुई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने १० मई को हुई संघर्षविराम समझौते के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

भारत की ओर से बातचीत की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने की, जबकि पाकिस्तान की ओर से मेजर जनरल काशिक अब्दुल्ला ने भाग लिया। यह बातचीत पहले दोपहर १२ बजे तय थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह शाम ५ बजे आरंभ हुई।

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भरोसा दिलाया कि पाक सेना संघर्षविराम का उद्घोषन नहीं करेगी। यह वार्ता उस समय हो रही है जब हाल ही में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (झेच) में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था।

गौरतलब है कि २२ अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में २६ निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी। इस हमले के जवाब में भारत ने ७ मई को सीमापार

कार्रवाई करते हुए नौ आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उसने युद्धविराम की पेशकश की। भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ९ और १० मई को पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और आम नागरिकों के निशाना बनाया था, लेकिन भारत के एंटी-ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीक, एयर डिफेंस हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को विफल कर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में डीजीएमओ स्तर की वार्ता से पहले सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों पर चर्चा हुई। भारत की ओर से की गई सभी जवाबी कार्रवाइयों 'ऑपरेशन सिंदूर' के अंतर्गत की गईं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शनिवार को संघर्षविराम की घोषणा के बाद से हालात में शांति देखी जा रही है। भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे से फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सहमति जताई है।